लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 764

07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा

764. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत के 60 बिलियन डॉलर के मानव निर्मित वस्त्र क्षेत्र की रीलों का चीन से अत्यधिक आयात हो रहा है और देश में कई बुनाई इकाइयों को बंद कर दिया गया है या उत्पादन में 20 प्रतिशत की कटौती करने के लिए बाध्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक तरफ तो देश में बुनाई इकाइयों को चीन से भारी सस्ते आयात का सामना करना पड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ एमएमएफ सूत का उत्पादन करने वाली कपड़ा मिलों को परीक्षण पर लाखों खर्च करके बीआईएस स्टैंड के लिए सूत की जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय एमएमएफ विनिर्माता चीन, थाईलैंड, कोरिया जैसे एमएमएफ उत्पादों में अधिक नवीनता नहीं ला सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में मानव निर्मित वस्त्र इकाइयों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): भारत के पास मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) सहित कच्चे माल का मजबूत आधार होने की सुविधा है। उद्योग एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र की क्षमता का भरपूर सदुपयोग करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो वस्त्र हेतु पीएलआई योजना और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन द्वारा विधिवत समर्थित देश में एक उभरता हुआ उद्योग खंड है। वस्त्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, पांच वर्षों की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। तकनीकी वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को मंजूरी दी गई है जो मुख्य रूप से एमएमएफ आधारित है।

गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को सक्रिय रूप से शुरू किया गया है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग अन्य देशों से भारत में आयात की डंपिंग के मामलों को संभालता है।

इसके अलावा, देश में एमएमएफ मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने "मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर वस्त्र सलाहकार समूह" की स्थापना की है, जिसमें संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के हितधारकों को शामिल किया गया है ताकि वे क्षेत्र के मुद्दों और समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सिफारिशें कर सकें और इसके विकास में मदद की जा सके। सरकार लगातार उद्योग के दोनों पक्षों, निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क में है और आवश्यकता के आधार पर उचित कार्रवाई कर रही है।

मंत्रालय भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की क्षमता का प्रदर्शन करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों को उजागर करने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए फरवरी, 2024 में एक वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट अर्थात भारतटेक्स 2024 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों की भी सहायता कर रहा है।

वस्त्र क्षेत्र के निर्यात-आयात रुझानों का विश्लेषण करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा वस्त्र मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ भी नियमित रूप से बातचीत की जाती है।

******